

पारदर्शी हो नियुक्ति प्रक्रिया

आखिरकार सरकार ने तीन समाह के भीतर पंजाब और हरियाणा उच्च व्यायालय के लिये नये मुख्य व्यायामीशी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी लेकिन दिल्ली उच्च व्यायालय जहां व्यायमूर्ति गति मितल पिछले साल 14 अप्रैल से कार्यावाहक मुख्य व्यायामीशी हैं, को अभी भी मुख्य व्यायामीशी का इंतजार है।

यहां यह तथ्य भी थी कि चौके मुख्य व्यायामीशी चार मई को सेलिनिट द्वारा रहे हैं, इसलिए इलाहाबाद उच्च व्यायालय के वरिष्ठतम व्यायामीशी कृष्ण मुरारी को इस उच्च व्यायालय का मुख्य व्यायामीशी नियुक्त किया जाये मगर सरकार ने इस पर अपनी मुहर लगाने में एक महीने से भी अधिक का वक्त लिया।

व्यायामीशी के घटना और नियुक्ति की कॉर्डेजियम प्रक्रिया वैसे तो करीब तीन दशक से विवाद का केवड़ बनी हुई है। पिछले करीब तीन साल से इस व्यवस्था पर असंतोष व्यक्त किया जा रहा है। राष्ट्रीय व्यायामीशी की नियुक्ति आयोग कानून निरस्त करने वाली सविधान पीठ के सदस्य व्यायमूर्ति जे. येलामेश्वर ने अपने फैसले में मोज़दा कॉर्डेजियम व्यवस्था की खासियतों को पहली बार पूरी साफगोई के साथ उत्तराधिकार किया था।

यही वजह है कि अब यह सवाल जोर पकड़ रहा है कि क्या व्यायामीशी के घटना और उक्तीकी नियुक्ति यों की सिफारिश करने वाली कॉर्डेजियम की प्री या पारदर्शी बालों की दिशा में कदम उठाये जाने के बावजूद प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा है। इसकी सिफारिशों को लेकर व्यायापिका के भीतर और बाहर आलोचनाएं हो रही हैं। उत्तराखण्ड उच्च व्यायालय के मुख्य व्यायामीशी के, एम. जोसेफ को पद्धतिकृत देकर शीर्ष अदालत में नियुक्त करने की कॉर्डेजियम की 10 जनवरी की सिफारिश लोटाये जाने के बाद सरकार के साथ ही कॉर्डेजियम की कार्यशैली को लेकर सार्वजनिक रूप से आलोचनाएं तेज हो गयीं।

व्यायमूर्ति जोसेफ की फाइल प्रधान व्यायामीशी के पास सरकार के नोट के साथ वापस आने के बाद कॉर्डेजियम की दो बैठकें हो चुकी हैं लेकिन अभी तक उनके नाम की फिर से सिफारिश नहीं की गयी है। इस बीच, पूर्व प्रधान व्यायामीशी तीरथ सिंह ठाकुर और आर. एस. लोढ़ा की सार्वजनिक टिप्पणियों के बाद केरल उच्च व्यायालय के व्यायामीशी पद से देवनिवृत्त होते वक्त व्यायमूर्ति पी. कमल पाणी की तत्काल टिप्पणियां इसका सबूत हैं कि व्यायामीशी की नियुक्ति यों की प्रक्रिया में सब कुछ ठीक नहीं है। व्यायामीशी की नियुक्ति के मामले में जाति और क्षेत्रीयता आदि को लेकर घल रही बहस के संदर्भ में उन्होंने यहां तक कहा कि वह इसमें यकीन नहीं करते कि प्रत्येक वर्धमान, जाति अथवा उपजाति को व्यायामीशी का पद अदायत किया जाना चाहिए। उन्होंने यह कहने में संकोच नहीं किया कि कॉर्डेजियम व्यायामीशी पद के लिये ऐसे वर्तीलों की सिफारिश करती है जो इसके लिये उत्तुक नहीं हैं।

हाल ही में कांग्रेस नेता पी. घिरंबरम ने इस गतिरौप का ठीकाकारी व्यायापिका पर फोड़े का प्रयास किया। उनका कहना था कि व्यायमूर्ति जोसेफ के बाम की फिर से सिफारिश करने का फैसला लेने के बावजूद इसे सरकार के पास भेजने के निर्णय को टालने के लिये फिलहाल तो व्यायापिका को ही जिम्मेदार ठहराया जायेगा। देश के आजाद होने के बाद 26 जनवरी, 1950 में उच्चतम व्यायालय के अस्तित्व में आने के समय से ही उच्च व्यायामीलों और उच्चतम व्यायालय के व्यायामीशी की नियुक्ति कार्यपालिका के माध्यम से राष्ट्रपति करने आ रहे थे परंतु व्यायामीशी की नियुक्ति की व्यवस्था में एस. पी. गुप्ता बनाम भारत सरकार प्रकरण में व्यायालय के 1982 निर्णय से कुछ बदलाव आया लेकिन अकू बूर 1993 में उच्चतम व्यायालय की व्यवस्था वे व्यायामीशी की नियुक्ति का काम कार्यपालिका से शीर्ष अदालत या कहें कि व्यायापिका ने अपने हाथ में ले लिया था।

अतः राष्ट्रपति ने इस प्रकरण से जुड़े सवालों पर 23 जुलाई 1998 को उच्चतम व्यायालय से राय मांगी। व्यायालय की सीधियां पीठ के 28 अकू बूर, 1998 को अपनी राय में कार्यपालिका को एकदम किनारे लगा दिया। चूंकि 68 साल में कार्यपालिका द्वारा व्यायामीशी की नियुक्ति के 32 साल के अनुभव और इसके बाद 36 साल तक कॉर्डेजियम व्यवस्था को लेकर उठ रहे विवादों के मद्देनजर महसूस किया जा रहा है कि वर्गमान पी या में व्यापक बदलाव की जरूरत है। शीर्ष अदालत के अकू बूर 2015 के फैसले में दिये गये विवरों के बाद भी पूरक मेमोरांडम आफ प्रोसीजर को अभी तक अतिम रूप नहीं दिया जाना भी अनेक सवालों को जन्म दे रहा है।

इसलिए उचित होगा व्यायामीशी के घटना, नियुक्ति और स्थानांतरण के लिये ऐसी व्यवस्था अपनाई जाये जो पूरी तरह पारदर्शी हो और जिसमें भाई-भतीजावाद के आरोप लगाने की गुंजाइश कम हो।

संपादकीय/खाना खजाना/राशिफल

साप्ताहिक
न्याय साक्षी

अधिकार संचाय तक

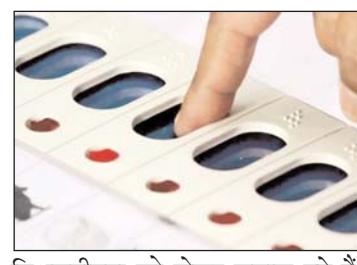
02

सियासी तपिश से बेहाल लोकतंत्र

समझ में नहीं आता चुनावी मौसम में ही इंवीएम से गडबड़ियों का भूत क्यों निकलता है? पहले कहां मर जाता है। उसे भी कोई भूत पकड़ रखता है जो चुनावी मौसम में छोड़ देता है। लोकतंत्र है, हो सकता है गडबड़ि को गडबड़ि पकड़ ले। कान में फूक मार दे, अभी कहां निकल रही है। बाहर तो भीषण गमीं पड़ रही हैं। टेपरेचर हाई हो रहा है।

आग बरस रही है। मतदान के दिन निकलते। ठीकरा किसी के भी सिर फोड़ देंगे। इंवीएम से गडबड़ियों का भूत निकलता है तो निकलते लेकिन ठीकरा तो अपने सिर पकड़ देंगे। सियासी एक-दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ते हैं तो बीच-बचाव में लोकतंत्र को आना पड़ता है। बीच-बचाव में स्थियास्ती तो अपना सिर बचा लेते हैं और लोकतंत्र का सिर पूट जाता है। लोकतंत्र का सिर पूट जाता है तो लोकतंत्र भूमिका भी मरहम-पट्टी नहीं करवते।

पिछले दो-तीन साल में इंवीएम जितनी बदनाम हुई है, उत्तीर्णों में मुक्ती भी बदनाम नहीं हुई होगी। कभी छेड़खानी के आरोप लगे तो कभी इसकी



विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठे हैं।

लेकिन लू पहली बार लगी है। इन दिनों मौसमी टेपरेचर इतना बढ़ रहा है कि पर्यावरण, कूलर व एसी गले में फॉसी का फदा लटकाए हुए हैं। ये तो गमीं से इतने तंग आ गए हैं कि इनका बार-बार खुदकुशी करने को मन करता है। लेकिन हर बार घंटा-घंटा स्विच ऑफ करके बचा लिया जाता है।

यह तो शुक्र है की इंवीएम के लू ही लगी। गमीं से तंग आकर खुदकुशी नहीं की। बरना सवाल ही नहीं उठते, सुलगते भी। जब सवाल सुलगते हैं तो आग उल्टते हैं। उल्टी आग किसी को भी निगल सकती है। मौसमी टेपरेचर की तरह रुक्ति भी नहीं होता है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जब बाकई में खतरे में होता है तो न तब कोई भी खतरा मोल नहीं लेता। सब पतली गली से निकल लेते हैं। लोकतंत्र में 'लोक' की हत्या हो रही है। जाती है। लेकिन 'तंत्र' के खरोंच भी नहीं आती।

गति से चलेगी। संभावना है आम चुनाव तक तो सियासी टेपरेचर अड़तालीस डिग्री सेल्प्रियस से ऊपर पहुंच जाएगा। अड़तालीस डिग्री सेल्प्रियस में लोकतंत्र का क्या हाल होगा? फिर भी लोकतंत्र जनतंत्र के लिए रेंगस्तान में सेना के जवान की तरह तैनात रहता है।

इंवीएम लू की चपेट में आई तो उसकी दूसरी इंवीएम बहन उसकी जगह आ गई। कल को लोकतंत्र लू की चपेट में आकर बीमार पड़ गया तो इसकी जगह कौन आएगा? लोकतंत्र के तो कोई भाई-भतीजा भी नहीं है जो आ जाएगा। परिवार भी नहीं है जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी विरासत में मिली सियासत की सीधियाँ चढ़कर चला आएगा। लोकतंत्र तो इक्लौटा है। सच पूछिए तो वे भी पूछने लगते हैं। आजपास नहीं हैं जो बात कोई भी खतरा मोल नहीं लेता।

एक बार कालिदास शास्त्रार्थ करने वाले पर अपना पूरा परिचय मिल जाएगा। लोकतंत्र के तो सियासी टेपरेचर के लिए निकल पड़े। कुछ देर बाद कालिदास ने बच्ची से कहा-मैं बलवान हूं। बच्ची उन्हें काफी जोर की आपस लगी, रास्ते में न कहा-मूझे बताइए कि इस संसार में कौन दो बलवान हैं। यदि एपाको उत्तर सही देता है तो आपको जल पिलाऊंगी। कालिदास ने कहा-इस प्रसन का उत्तर तुम ही दे दो और मुझे जल पिला दो।

उपचुनावों की कसक



पर सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्य में राजग का चेहरा बताया गया है। इसी भीच खबर आई है कि बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री को फसल बीमा योजना को खारिज करके नई फसल बीमा योजना लागू की है। राजग के घटक दलों जद (यू) और शिवसेना के तेवरों ने देश की राजनीति को गमाया है। यहां है कि इस बार भाजपा की राह आसान नहीं है। विपक्ष ने घटक दलों जद (यू) और शिवसेना के तेवरों ने देश की राजनीति को गमाया है। यहां है कि इस बार भाजपा की राह आसान नहीं है। विपक्ष ने घटक दलों जद (यू) और शिवसेना के तेवरों ने देश की राजनीति को गमाया है। यहां है कि इस बार भाजपा की राह आसान नहीं है। विपक्ष ने घटक दलों जद (यू) और शिवसेना के तेवरों ने देश की राजनीति को गमाया है। यहां है कि इस बार भाजपा की राह आसान नहीं है। विपक्ष ने घटक दलों जद (यू) और शिवसेना के तेवरों ने देश क